



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 11 जून, 2004/21 ज्येष्ठ, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जून, 2004

संख्या एस० टी० ई०-ए(3)-4/2003.—राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या ई० डी०एन० (एस एण्ड टी) ए (3) 5/98 दिनांक 26-11-1998 द्वारा व्यापारियों, फुटकर विक्रेताओं और विक्रेताओं (बैंडरज) द्वारा ट्रेडिड। विक्रित माल (वस्तुओं) की पैकेजिंग के लिए पुनः चकित प्लास्टिक से विनिर्मित रंगीन पोलिथीन कैरी बैगों के, हिमाचल प्रदेश राज्य में, प्रयोग पर 1 जनवरी, 1999 से प्रतिबन्ध अधिरोपित किया था।

और राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि समस्त प्रकार, आकार और मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैगों का प्रयोग किया जा रहा है और उन्हें यहाँ-वहाँ वन भूमि, सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों (ड्रेन्ज) इत्यादि सहित हर जगह पर अव्यवस्थित रूप से फेंका जा रहा है जिसके कारण पर्यावरिक अवक्रमण और स्वच्छता से सम्बन्धित गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

और प्लास्टिक कैरी बैग्स अव्यवस्थित रूप से फेंके जाने को कम करने के लिए और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के निवारण के लिए राज्य सरकार इस मत की है कि जीव-अनाशित सामग्री से बने कैरी बैगों के विनिर्देश अधिकथित किए जाने अति आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 7 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह अपेक्षा अधिरोपित करते हैं कि समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में सभी प्रकार की वस्तुओं के स्टाकिस्ट, ट्रेडर, फुटकर विक्रेता तथा विक्रेता (बैंडरज) हिमाचल प्रदेश जीव-अनाशित कूड़ा-कचरा नियन्त्रण अधिनियम, 1995 की अनुसूची में सूचीबद्ध जीव-अनाशित सामग्री से बनाए उन कैरी बैगों का प्रयोग नहीं करेंगे जिनकी मोटाई 70 माइक्रोन से कम हो और आकार 12" X 18" से कम हो।

कोई भी व्यक्ति जो उपर्युक्त अपेक्षा का भंग कारित करता है वह उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शास्तियों के लिए उत्तरदायी होगा।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुनः आदेश देते हैं कि यह अपेक्षा, लोक हित में, समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में 14 जून, 2004 से प्रवृत्त होगा।

आदेश द्वारा,

संजीव गुप्ता,  
सचिव।

## SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 4th June, 2004*

No. STE-A(3)-4/2003.—Whereas the State Government *vide* its notification No. EDN (S&T)A(3) 5/98 dated 26-11-1998, imposed prohibition on the traders, retailers and vendors in the State of Himachal Pradesh for using the coloured polythene carry bags manufactured from recycled plastic, for packaging the goods traded/sold by them, with effect from the 1st January, 1999.

And whereas, it has come to the notice of the State Government that the plastic carry bags of all types, sizes and thickness are being used and being thrown indiscriminately every where including forests land, public places, roads, drains etc. thereby causing serious problems related to sanitation and environmental degradation.

And whereas, in order to reduce indiscriminate throwing of plastic carry-bags and preventing insanitary conditions, the State Government is of the view that there is an urgent need to lay down specifications of carry bags made of non-biodegradable materials.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred upon him under clause (h) of Section 7 of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, is hereby pleased to impose a requirement that the stockists, traders, retailers and vendors, of all kinds of commodities, within the entire State of Himachal Pradesh shall not use carry-bags made of non-biodegradable material listed in the Schedule to The Himachal Pradesh Non-Bio-degradable Garbage (Control) Act, 1995, having thickness less than 70 microns and size less than 12"×18".

Any person causing breach of the aforesaid requirement shall be liable for penalties as per the provisions of the Act *ibid*.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that this requirement shall come into force with effect from 14th June, 2004 in the entire State of Himachal Pradesh, in the public interest.

By order,

SANJEEV GUPTA,  
Secretary,